



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1940 (श10)

(सं० पटना 444) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2019

सं० 02/रेगु.-01-506/2018-363
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

5 मार्च 2019

विषय:- राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को ईख मूल्य के ससमय भुगतान सुनिश्चित कराने के निमित्त राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में इनके द्वारा पेराई सत्र 2018-19 में क्रय किये गए गन्ने पर 12.50 रु. प्रति क्विंटल की दर से कुल 112.50 करोड़ (एक सौ बारह करोड़ पचास लाख) रु० ईख मूल्य अनुदान का चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध राशि एवं शेष राशि का वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त बजट से भुगतान करने की स्वीकृति तथा पेराई सत्र 2018-19 के लिए ईख "क्रय-कर" (Purchase Tax) की अदायगी से छूट प्रदान करने एवं क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन ईख मूल्य के दर का 0.20% का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति।

राज्य की चीनी मिल संगठन (बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन) द्वारा सूचित किया गया है कि विगत पेराई सत्र से अबतक चीनी की कीमतों में आयी भारी गिरावट, चीनी की रिकवरी में गिरावट एवं राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की अत्यधिक उत्पादन के कारण गन्ने के मूल्य एवं चीनी के बिक्री से प्राप्त होने वाले राशि में काफी mismatch की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके कारण चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गयी है तथा उन्हें किसानों को ईख मूल्य भुगतान करने में कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत चीनी मिलों को आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने, गन्ना कास्तकारों को उनके उत्पाद के लिए नियमित रूप से गत वर्ष के दर के अनुरूप ईख मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चालू पेराई सत्र 2018-19 के लिए चीनी मिलों को ईख क्रय कर की 1.75 रु०/क्विंटल की दर से अदायगी से छूट/विमुक्ति एवं भुगतये क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन ईख मूल्य के दर का 0.20% के रूप में पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है (संबंधित अधिसूचना अलग से निर्गत किये जा रहे हैं)।

इस निमित्त राज्य योजना से अनुमानित 112.50 करोड़ रुपये ईख मूल्य अनुदान के रूप में चीनी मिलों को भुगतये होगा जिसका भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध राशि से की जायेगी एवं शेष राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपलब्ध होने वाले बजट आवंटन से की जायेगी।

2. उपरोक्त कंडिका में अंकित राशि की विमुक्ति एवं वितरण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-
- (i) राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2018-19 में 31 जनवरी, 2019 तक क्रय किये गये गन्ने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि की उपलब्धता के अनुसार अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
 - (ii) राज्य की चीनी मिलों को यह विकल्प खुला रहेगा कि वे पेराई सत्र 2017-18 एवं/या पेराई सत्र 2018-19 में क्रय किये गये ईख की मात्रा पर उक्त ईख अनुदान का समायोजन कर सकेंगी।
 - (iii) पेराई सत्र 2018-19 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा जितनी मात्रा में गन्ना क्रय की जायेगी वह उनकी अनुदान की गणना के लिए अधिकतम सीमा होगी।
 - (iv) निर्धारित शर्तों के अनुरूप ईख मूल्य का भुगतान नहीं करने, उसमें किसी प्रकार का विचलन किये जाने के प्रमाण प्राप्त होने की स्थिति में अनुदान स्वरूप उपलब्ध करायी गयी सम्पूर्ण राशि को मिल से वापस ले ली जायेगी तथा उन मिलों के विरुद्ध सख्त दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।
 - (v) मिलों को उपलब्ध करायी गयी अनुदान की राशि का उपयोग पेराई सत्र 2017-18 एवं 2018-19 के लिए शेष भुगतेय ईख मूल्य के भुगतान के मद में किया जायेगा। प्राप्त अनुदान की राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित चीनी मिलों द्वारा विभाग एवं स्थानीय ईख पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (vi) चीनी मिलों द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय **undertaking** देना होगा कि प्राप्त होनेवाले ईख मूल्य अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग किसानों के ईख मूल्य भुगतान के मद में होगा। ईख क्रय का सत्यापन स्थानीय ईख पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
 - (vii) राज्य योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के बजट प्रावधान अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष से की जाएगी—
सामान्य श्रेणी— मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष-राज्य योजना, लघुशीर्ष-201- चीनी, उपशीर्ष-0103, विषयशीर्ष-3301-अनुदान, विपत्र कोड-45-2852082010103 मद चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में उपलब्ध उद्व्यय एवं उपबंध से स्वीकृत कर निकासी एवं व्ययन किया जायेगा।

3. उपरोक्त लाभ बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्र आरक्षण के माध्यम से राज्य के गन्ना कृषकों से गन्ना क्रय करनेवाली राज्य के बाहर के चीनी मिलों को भी उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 सुधीर कुमार,
 प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 444-571+200 डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>